संख्या-37/2019/682/सैंतीस-2-2019-1(3)/2014टीसी।

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-30 मार्च, 2019

विषयः- **अनुदान संख्या-83 के अधीन डिजीज फ्री जोन की स्थापना (60 प्रति.के.पो.) (एफ.एम.डी.सी.पी.) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-571/सा0-1/एक्स-160/एफ.एम.डी.-सी.पी.(एस.सी.एस.पी.)/2018-19, दिनांक-13.03.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0103-डिजीज फ्रीजोन की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.) के मानक मद 04-यात्रा व्यय में सम्भावित बचतों से उक्त लेखाशीर्षक के ही मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0-53.33 लाख (रूपये तिरपन लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 के अनुसार पुनर्विनियोजित किये जाने की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) बचतों के सही होने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोजित की जा रही है उस मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में किसी अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) जिस मानक मद में धनराशि पुनर्विनियोजित की जा रही है, उसमें यह संगत शासनादेश/प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जायेगी।

(4) पुनर्विनियोजित की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग यह सुनिश्चित करेगे कि इस हेतु पूर्व में किसी योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(8) एफ.एम.डी. टीकाकरण हेतु प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि का क्रय विद्यमान संगत शासनादेशों व निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) प्रदेश में चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। अतः निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि इससे चुनाव आचार संहिता का किसी भी दशा में उल्लंघन न हो।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0103-डिजीज फ्रीजोन की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.)-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-344/दस-2019, दिनांक-29.03.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-प्रपत्र बी.एम.-9

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-37/2019/682(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मँत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in